उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) से (ग) : पूर्ण विवरण जैसे उपक्रम का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु, विदेशी कंपनियों को दिये गये सभी औद्योगिक लाइसेंसों सहित लाइसेंसीकृत क्षमता "वीकली बुलैटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंस एक्सपोर्ट लाइसेंसज एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज" में दी गई है जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

उपभोक्ता माल की वस्तुओं में जिन वस्तुओं का उत्पादन ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा सकता है वे ये हैं जैसे चमड़े के जूते, दियासलाई तथा कपड़े धोने का साबुन ।

दिसम्बर, 1977 में संसद् के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति विवरण में अन्य बातों के साथ साथ यह स्पष्ट बता दिया गया है कि सरकार देश के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप बड़े गृहों की गतिविधियों को विनियमित करेगी । बड़े एकक चाहे वे बड़े गृहों के हों अथवा न हों किन्तु जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करने में लगे हुए हैं, उनकी क्षमता में विस्तार नहीं होने दिया जायेगा । ऐसे क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों तथा एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पड़ने वाली कम्पनियों का प्रवेश उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से विनियमित होता है ।

Time Allotted on News Bulletin Re. Bengal Flood Situation

2496. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the total time allotted by the All India Radio, Delhi in their all India news bulletins to cover the recent flood situation in West Bengal where out of 16 districts 12 districts were inundated and 15 million people had been severely affected by the floods, while estimated crops covering 2.8 million acres had been destroyed; and

(b) the time allotted for the other flood affected States, state-wise?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b). In the main morning, afternoon and evening bulletins during the period June to October, 1978, the time devoted to news items relating to floods in the affected States was as follows:—

Bihar	. 62	minutes
Delhi	. 61	,,
Orissa	6	,,
Uttar Pradesh	98	,,
West Benga	98	,,

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी युवकों को रोजगार

2497. **श्री उग्रसेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को कपड़ा बेचने के लिए लाईसेंस देने की योजना कब से लागू की गई है और किन किन राज्यों के किन किन जिलों में यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने बेरोजगार युवकों को कार्य पर लगाया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को कमीशन के आधार पर बिक्री-प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने की योजना सितम्बर, 1978 से आरम्भ की गई थी । यह योजना राष्ट्रीय वस्त्र निगम के निम्नलिखित स्थानों पर स्थित प्रभावीय कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है : —

1. नई दिल्ली
2. चण्डीगढ़
3. कानपुर
4. वाराणसी
5. जयपुर
6. पटना
7. कलकत्ता
8. भुवनेश्वर
9. बम्बई
10. इंदौर
11. नागपुर
12. अहमदाबाद
13. मद्रास
14. तिरुचि